

# ① प्रधानमंत्री

ब्रिटिश मॉडल पर भारतीय संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् को वास्तविक कार्यपालिका बनाया गया। प्रधानमंत्री की अपनी मंत्रिपरिषद् के बचन का अधिकार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् संसद के प्रति उत्तरदायी है, उपर्युक्त व्यवस्था में मंत्रिपरिषद् महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। लोकसभा में पार्लियामेण्टरी गवर्नमेंट इन इंग्लैंड में लिया है कि 'मंत्रिपरिषद् के निर्माण का यह केंद्र बिन्दु है मंत्रिपरिषद् के जीवन का यह केंद्र बिन्दु है और मंत्रिपरिषद् की मृत्यु का केंद्र बिन्दु है।' क्रासमैन के उद्धृत 'द्वितीय महासुद्ध' के पश्चात् के वर्षों में मंत्रिपरिषद् शक्तिशाली प्रधानमंत्री शालन गुणाधी के परिवर्तित हो गई है। भारत में प्रधानमंत्री के अति उपर्युक्त पार्लियामेण्टरी मांग होगी है क्योंकि हमारी व्यवस्था की ब्रिटिश व्यवस्था होती है। भारतीय प्रधानमंत्री के विषय में यह आरोप लगाया जाता रहा है प्रधानमंत्री तानाशाह होता जा रहे रहा है जिससे मंत्रिपरिषद् सरकार में प्रधानमंत्री सरकार में बदली जा रही है।

यह आरोप शायद इलाके लगाया जा रहा है क्योंकि भारत में स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात् प्रधानमंत्री मुख्य प्रशासक, प्रमुख नीति निर्माण, मुख्य राजनीतिक एवं शक्ति निर्माण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। प्रधानमंत्री के पद पर प्रभावशाली व्यक्ति के हवी व्यक्ति रहे हैं। जनता के प्रधानमंत्री के व्यक्ति के प्रभाव से लोकसभा चुनावों के परिणाम दिए हैं। 56 प्रकार 56



2) उपरोक्त जनता की अपेक्षाओं की प्रधानमंत्री को  
बढ़ा है। जनता प्रधानमंत्री को राष्ट्र का नेता एवं  
सर्वोपरि नेतृत्व मानती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री  
की शक्तियाँ बढ़ी होती रही हैं।

प्रधानमंत्री को तानाशाही इसलिए कहा जाता है कि  
भारत के अधिकांश समय तक केंद्रीय दम का संतुलन  
में बहुत रहा साथ ही नरेश परिवार का वर्चस्व भी  
बना रहा। उक्त दौरान PM ने जो याद रह मंत्रिमण्डल  
से पारित कराया तथा कानून बनवाया। इसके अतिरिक्त  
जहाँ भी राष्ट्रों के उनके दम की सरकारें रही उनके  
कार्यक्रम, मुख्यमंत्री के चयन, राज्यपालों की  
निर्मुक्ति आदि से उक्त उच्च अपने दम के अहंकार के  
रूप में प्रभावित किया। शालका अर्थात् व्यवस्था के  
प्रभाव के कारण शक्ति शक्ति शक्ति के समय यह  
प्रति अत्यधिक बढ़ी। आपात स्थिति के समय  
यह पूर्ण तानाशाह बन गई।

जनता शासन के अल्पशासन के तथा उनके  
बाद गौरी केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्रियों ने तानाशाह  
बनने का प्रयास नहीं किया था कहा जाए कि  
अतुल्य परिस्थितियाँ प्राप्त नहीं हुई।

विद्वानों का मत है कि भारत में प्रधानमंत्री  
अनेक प्रकार नियंत्रणों में कार्य करता है अतः यह  
यह कहना ठीक नहीं है कि प्रधानमंत्री व्यवस्था  
स्थापित होती जा रही है। प्रधानमंत्री के अंतर्निहित  
संविधान, संघ व्यवस्था संसदीय नियंत्रण, दलीय  
नियंत्रण एवं जनमत का नियंत्रण सर्वत्र बना रहता है।



(3) जिनसे वह निरङ्कुश नहीं हो पाता फिर भी आइएट जैनसल के अनुसार "प्रधानमंत्री के पद की स्थिति अवश्य बेटी होगी जो उच्च पद की ग्रहण करने वाला व्यक्ति बनाना चाहेगा और अन्य मंत्री उच्च बनने देंगे"।

परम्परागत स्थिति: - बीबीसी टीवी के आन्तक दस्तावेजों के आधार पर प्रधानमंत्री की शक्ति का प्रभाव प्रभावित हुई → पहला गोलमेलाइजेशन के कारण लोक कल्याणकारी नीतियों के परिवर्तन की ओर आवश्यकता और खिलडी के कटौती कला जो अक्रियता परिस्थिति बना रही थी तथा शाला भाती प्रशासनिक विभाग के लिए केंद्रों को पौरे विषयों के रियायत देने की प्रवृत्ति की ओर मुकाबला।

→ दूसरा गठबंधन के कारण क्षेत्रीय भागी एवं दलों के दबाव का सामना करने की चुनौती आयी। ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय राजनीतिक संयमकोपी राज्यापेक्षी हो गई और प्रधान मंत्री की स्थिति अपनी शक्ति नहीं रही जैसी कि श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ के थी। 1990 का दशक अत्यन्त अस्थिरता वाला समय था उदाहरणार्थ 1996 में अरुण जी की सरकार मात्र 13 दिन चल पायी। पुनः 1998 में वाजपेयी की सरकार में पुनः वनी एन.डी.ए. की सरकार 22 दिनों का गठबंधन था। 1999 में भा.ज.पा. की स्थिति में सुधार आया फिर भी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन के दम में उन्हें मिलना पड़ा। फल यह निकला कि भा.ज.पा. अपने श्रेष्ठता का साधन नहीं कर सकी स्वयं चतुर्मुख झड़क योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना के बावजूद 2004 का चुनाव नहीं जीत सकी। 2004 में कांग्रेस गठबंधन सरकार क्षेत्रीय दलों के दबाव में रही और अपनी नीतियों लागू नहीं कर सकी। फिर भी मनरेगा, सूचना का अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जिनके चलते 2009 में यह पुनः सत्ता में आयी।

परन्तु भा.ज.पा. की धारणात्मक शक्तों की नीति में परिवर्तन का अन्त हो नहीं हुआ आया। फलस्वरूप 2014 के बाद PM की मजबूत स्थिति में आ गई और अन्य कठोर निर्णय लेने में सफल रहे। गठबंधन के क्षेत्रीय दलों का प्रभाव खत्म हो गया। 2014 में स्थिति और मजबूत हो गयी। आज भारत में PM अत्यन्त शक्तिशाली हो चुका है और इसी कारण सभी लोकतान्त्रिक संस्थाओं पर PM का दबाव है तथा नोटबंदी, जी.एस.टी., धारा 370 का एकांग्रान्त धूल फेंकना निर्णय लेने में सफल है। प्रम. M. P. Singh के नेतृत्व में लिखा है कि वर्तमान स्थिति में मजिस्ट्रेट के बदले में उनके सामने नरमस्वक रहे हैं।